2024 में मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या 33 प्रतिशत कम

अर्थव्यवस्था पर संकट : भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से किया किनारा

नई दिल्ली। भारत और पड़ोसी मालदीव के बीच हाल के दिनों में जारी खटास के बीच द्वीपीय राष्ट्र में पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों बहुत हद तक गिर गई है। इसका असर मालदीव के पर्यटन उद्योग पर पड़ना शुरू हो गया है और मांग उठने लगी है कि भारत के साथ संबंधों को जल्द से जल्द सुधारा जाए। 2023 में मालदीव पहुचंने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक थी, पर 2024 भारतीय पर्यटकों की संख्या छठे नंबर पर पहुंच गई है। इससे पर्यटन पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

» पर्यटन उद्योग पर ही आधारित है मालदीव की अर्थव्यवस्था

मालदीव के तीन अधिकारियों की ओर से सोशल मीडिया पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया था। बीते 6 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर भारत के पश्चिमी तट पर प्राचीन लक्षद्वीप के द्वीपों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे।

मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में 17 लाख से अधिक पर्यटकों ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया, जिनमें से 2,09,198 से अधिक आगंतुक भारतीय थे, इसके बाद रूसी (2,09,146) और चीन (1,87,118) थे। 2022 में भारतीय आगंतुकों की संख्या 2.4 लाख से अधिक थी, जबकि 2021 में 2.11 लाख से अधिक भारतीयों ने मालदीव के लिए उड़ान भरी। महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खुले कुछ देशों में मालदीव भी था और उस अवधि के दौरान लगभग 63,000 भारतीयों ने उस देश का दौरा किया। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 2024 में पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत छठे स्थान पर है। 2020 से मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार पहले स्थान पर रही है। भारतीय पर्यटक महामारी के समय में भी द्वीपीय राष्ट्र का दौरा कर रहे थे। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है 2 मार्च 2024 तक 27,224 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे, जो पिछले साल की तुलना में 33 प्रतिशत कम है, जब इस अवधि में 41,224 लोग मालदीव पहुंचे थे। मालदीव का पर्यटन उद्योग भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में आई ताजा खटास से चिंतित है और इस स्थिति में बदलाव की मांग कर रहा है। ऑफ-पीक सीजन के दौरान मालदीव में पर्यटन से संबंधित प्राप्तियों को बनाए रखने में भारत कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह बताते हुए एक समाचार पोर्टल Sun.mv ने कहा भारतीय यात्रियों और यूरोपीय यात्रियों के पर्यटन में एक काउंटर-ट्रैवल पैटर्न है। इसका मतलब है कि भारतीय पर्यटक गर्मी के दौरान मालदीव में अक्सर आते हैं, इस दौरान यूरोपीय पर्यटकों की संख्या में कमी आती है। दूसरे शब्दों में, भारतीय पर्यटक मालदीव के पर्यटन उद्योग के ऑफ-पीक सीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिलर है।

पेट्रोल-डीजल 2 रुपए सस्ता

22 महीने बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने घटाए दाम

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कीमतें 15 मार्च सुबह 6 बजे से कम हो गई हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने बीते दिन दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था। अब दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

भोपाल में पेट्रोल के दाम 106.47 रुपए तो डीजल 91.84 रुपए प्रति लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 104.88 रुपए जबकि डीजल 90.36 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने बीते दिन पेट्रोल-डीजल पर 2 प्रतिशत वैट भी कम किया था, जिसके चलते यहां पेट्रोल 3.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3.36 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है।इससे पहले पेट्रोल-डीजल के दाम 2022 में कम हुए थे। सरकार ने 21 मई 2022 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। नए दाम 22 मई से लागू हुए थे। हालांकि, अभी जो दाम घटाए गए हैं उसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कम किए हैं। ये कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे दामों को रिवाइज करती हैं।जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी। 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया।

अभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।

वित्त मंत्रालय का सरकारी बैंकों को निर्देश- गोल्ड लोन की समीक्षा करें

कर्ज के वितरण में गड़बड़ियां

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों से सोने के गहनों के एवज में दिए गए कर्ज की स्थिति की समीक्षा करने को कहा है। कई मामलों में नियमों का अनुपालन न होने का मामला सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस ने सरकारी बैंकों को हाल में लिखे पत्र में कहा कि इस समय कर्ज से संबंधित प्रणाली और प्रक्रियाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

डीएफएस सचिव विवेक जोशी ने कहा, हमने बैंकों से सोने के एवज में दिए गए लोन की व्यापक समीक्षा करने को कहा है। गारंटी के बिना सोने के एवज में कर्ज का वितरण, शुल्क संग्रह और नकद में भुगतान को लेकर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन्हें दुरुस्त करना जरूरी है। डीएफएस ने बैंकों से एक जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2024 तक की अवधि के लोन की गहन समीक्षा करने को कहा है।

आंतरिक नीतियों का पालन जरूरी- समीक्षा का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गोल्ड लोन बैंकों की नियामकीय और आंतरिक नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं। विभाग के समक्ष ऐसे कर्ज के संबंध में नियमों का अनुपालन नहीं होने के मामले सामने आए हैं।

बिना शुल्क के सोना आयात कर सकेगा आरबीआई - केंद्र ने आरबीआई को शुल्क का भुगतान किए बिना सोना आयात की मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य केंद्रीय बैंक के लिए सोना आयात की लागत को कम करना है।

क्विक सप्लाई तीसरी सबसे बड़ी चुनावी बॉण्ड खरीदार

» रिलायंस से संबंध का दावा, पर कंपनी ने नकारा

नई दिल्ली। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड चुनावी बॉण्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दान करने वाली तीसरी सबसे बड़ी दानकर्ता है। क्विक सप्लाई नवी मुंबई के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) के पंजीकृत पते वाली कंपनी है। दावा किया जा रहा है कि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी है पर इस कंपनी का नाम अब तक कम ही लोगों ने सुना है

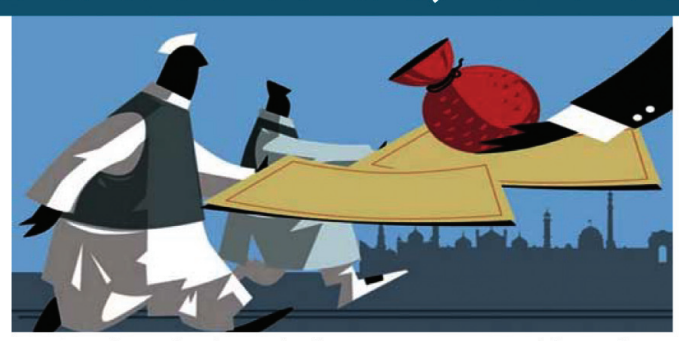

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 और 2023-24 के बीच 410 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड खरीदे। हालांकि, रिलायंस ने कहा है कि यह कंपनी रिलायंस की किसी भी इकाई की सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, क्विक सप्लाई के अलावे एक अन्य कम प्रसिद्ध लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1,368 करोड़ रुपये और हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 966 करोड़ रुपये राजनीतिक पार्टियों को दिए हैं। सार्वजनिक की गई जानकारी के अनुसार क्विक सप्लाई गोदामों और भंडारण इकाइयों का निर्माण करता है। इस गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी का नौ नवंबर 2000 को 130.99 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ निबंधन कराया गया था। इसकी चुकता पूंजी 129.99 करोड़ रुपये है। अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 में कंपनी का राजस्व 500 करोड़ रुपये से अधिक था। हालांकि कंपनी के मुनाफे का आंकड़ा ज्ञात नहीं है।

आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम में छंटनी की खबर

20 प्रतिशत कर्मचारी निकाले जा सकते हैं

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से परिचालन बंद करने के निर्देशों के बाद 15 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ज्यादातर सेवाएं बंद होनी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने 20 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे जुड़े दावे किए जा रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने कई डिविजन जिनमें ऑपरेशन या परिचालन इकाई भी शामिल है, में छंटनी की तैयारी कर ली है। दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक में फिलहाल 2,775 कर्मचारी हैं।

यूनिटेक के पूर्व निदेशक को हाईकोर्ट से आत्मसमर्पण करने का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूनिटेक के पूर्व निदेशक रमेश चंद्र को शनिवार (16 मार्च को) को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वह डेढ़ साल के लिए अंतरिम जमानत पर थे। उच्च न्यायालय ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह निर्देश दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी बीमारी जानलेवा नहीं है और उसका जेल में इलाज संभव है। हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रमेश चंद्र के उपचार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उनका समय-समय पर और सप्ताह में कम से कम दो बार मूल्यांकन किया जाएगा। वह घर खरीदारों से जुड़े फंड को डायवर्ट करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी हैं। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों इस साल हांगकांग और सिंगापुर की तुलना में अधिक वेतन वृद्धि मिल सकती है। विश्लेषकों के अनुसार चीन की वृद्धि दर धीमी होने के कारण कंपनियां देश के आर्थिक उछाल का फायदा उठा सकती हैं। विश्लेषक सारा जेन महमूद ने कंसल्टिंग फर्म एऑन के सर्वेक्षण आंकड़ों का हवाला देते हुए शुक्रवार को एक नोट में लिखा कि 2024 में भारत में वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों का वेतन 10 प्रतिशत बढ़ सकता है। जबकि अहम वित्तीय केंद्रों हांगकांग और सिंगापुर में वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों को 4त्न की वेतन वृद्धि ही मिल सकती है।

एयर इंडिया भवन महाराष्ट्र सरकार के हवाले, केंद्र ने दी मंजूरी, 1,601 करोड़ रुपये में हुआ है सौदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई स्थित एयर इंडिया की प्रतिष्ठित इमारत के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। मुंबई के नरीमन प्वाइंट पर स्थित एयर इंडिया की इमारत को महाराष्ट्र सरकार ने 1,601 करोड़ रुपये में खरीदा था। भारत सरकार ने एयर इंडिया की मुंबई स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग को 1601 करोड़ रुपये में महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मंत्री समूह 298.42 करोड़ रुपये के बकाये को माफ करने पर सहमत हो गया है। जिसे एआईएएचएल को दिया जाना था। नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की कंपनी एआईएएचएल की स्थापना 2019 में एयर इंडिया के नन कोर असेट्स और कर्जों को धारण करने के लिए की गई थी। जमीन और भवन समेत एयर इंडिया की 14,718 करोड़ रुपये मूल्य की नन कोर असेट्स (गैर-प्रमुख संपत्ति) एआईएएचएल को तब हस्तांतरित की गई थी। सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया की बिक्री से पहले इसका गठन किया था। सरकार ने 27 जनवरी, 2022 को एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह को हस्तांतरित कर दिया था, जिसने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर 1974 में निर्मित इस इमारत का उपयोग अब इसके कार्यालय स्थल के रूप में किया जाएगा। 23 मंजिला इमारत में सरकारी कार्यालयों के लिए करीब 46,470 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध होगी। मंत्रालय में 2012 में आग लगने के बाद, दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय भवन के चार प्रमुख विभाग जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, और ग्रामीण विकास- जीटी अस्पताल से संचालित हो रहे हैं। इन विभागों को अन्य विभागों के साथ एयर इंडिया भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है।

आईएमएफ के ऋण के लिए पाकिस्तान के दावों की खुली पोल, बैठक में मिशन ने अधिकारियों को फटकारा

कराची। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के उस दावे पर नाराजगी जाहिर की है कि जिसमें पड़ोसी देश ने वैश्विक ऋणदाता की ओर से होने वाली समीक्षा से पहले ही सभी संरचनात्मक मानकों और लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक टीम तीन अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की 1.1 अरब डॉलर की अंतिम किश्त जारी करने से पहले बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार आईएमएफ के मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर और उनके सहयोगियों ने इस बात पर नाखुशी जताई कि वित्त मंत्रालय ने तीन अरब डॉलर के स्टैंडबाय अरेंजमेंट प्रोगाम (एसबीए) के तहत समीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इसके निष्कर्ष के संबंध में बयान जारी कर दिया। इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक हैंडआउट में घोषणा की थी कि आईएमएफ से कोई प्रतिक्रिया मिलने से पहले उन्होंने सभी मानकों और लक्ष्यों को पूरा कर लिया है।

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ समीक्षा मिशन ने समीक्षा वार्ता के पहले सत्र में वित्त मंत्रालय की टीम को फटकार लगाई और इसके बाद वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आया कि जवाब कैसे दिया जाए। उसके बाद, वित्त मंत्री औरंगजेब ने आईएमएफ मिशन को बताया कि इस पर ध्यान दिया है और भविष्य में इस तरह की घटना कभी नहीं दोहराई जाएगी। पाकिस्तान और आईएमएफ ने दूसरी समीक्षा पूरी करने और आर्थिक व वित्तीय नीतियों के ज्ञापन (एमईएफपी) पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत शुरू की है। इसके बाद अप्रैल 2024 के दूसरे सप्ताह में फंड के कार्यकारी बोर्ड के समक्ष 1.1 बिलियन अमरीकी डालर की अंतिम किश्त जारी की जाएगी। आईएमएफ की टीम ने 9,415 अरब रुपये के वांछित वार्षिक कर संग्रह लक्ष्य हासिल करने के लिए अंतिम तिमाही (अप्रैल-जून) के आंकड़ो के बारे में भी पूछताछ की। आईएमएफ की टीम ने खुदरा विक्रेताओं के लिए सरलीकृत कर योजना का अनावरण करने के लिए सटीक समय सीमा के बारे में पूछा। उन्होंने इस संबंध में मौजूदा शासन की राजनीतिक इच्छाशक्ति के बारे में भी पूछताछ की। इस दौरान अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे थे।

देश का गेहूं भंडार 2018 के बाद पहली बार 100 लाख टन से नीचे

» 3.20 करोड़ टन तक पहुंच सकती है खरीद

नई दिल्ली। देश के गेहूं भंडार में इस साल तेज गिरावट हुई है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के पास रखे गेहूं का भंडार घटकर 97 लाख टन तक पहुंच गया है। यह गिरावट दो साल से सरकारी खरीद के सीमित रहने से देखने को मिली है। दूसरी ओर, चावल के भंडार भरे हुए हैं। एफसीआई के पास चावल बफर सीमा के दोगुना से ज्यादा है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भंडार से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की थी। इससे भंडार में और कमी आ गई। 97 लाख टन के साथ ही मौजूदा गेहूं भंडार जरूरी सीमा से काफी ऊपर है। नियमों के मुताबिक सरकार के भंडार में पहली अप्रैल को 74.6 लाख टन गेहूं रहना चाहिए।

गेहूं की खरीद का सीजन पहली मार्च से शुरू हो चुका है। इस साल सरकारी खरीद दो साल के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूं की खरीद 3.20 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस सीजन में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रह सकता है। एक साल में सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कई बार में 90 लाख टन गेहूं बाजार में उतारा था।